

पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम हमारी शर्तों पर होगा, पीएम ने एनएसए और एस जयशंकर से कर दिया था साफ

नई दिल्ली, 10 मई। भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर अपनी शर्तों पर ही सहमत होने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और एयर आईएसआई प्रमुख असीम मलिक ने भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के साथ संवाद शुरू करने की कोशिश की। हालांकि, सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों को यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी युद्ध विराम केवल हमारी शर्तों पर ही आगे बढ़ेगा। विदेश सचिव के



अनुसार, पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने शुक्रवार को 15:35 बजे कल्ल पर अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया। बातचीत के दौरान, दोनों पक्षों ने

17:00 बजे कल्ल से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों की ओर से संघर्ष

विराम लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। दोनों DGMO स्थिति की समीक्षा करने के लिए 12 मई को 12:00 बजे IST पर फिर से बात करने वाले हैं।

घोषणा से पहले कई दिनों तक, ठरअ अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर संघर्ष विराम प्रक्रिया पर अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत में लगे रहे। बातचीत के दौरान, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बारीकी से अपडेट रखा। भारत और पाकिस्तान के बीच बिना किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के संघर्ष विराम पर द्विपक्षीय रूप से सहमति बनी। यह पाकिस्तानी DGMO ही थे जिन्होंने दिन में पहले भारत को कॉल की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः सफलता मिली।

आज हर भारतीय सरकार के सामर्थ्य को महसूस कर रहा है: उपराष्ट्रपति धनखड़

नई दिल्ली, 10 मई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को कहा कि आज हर भारतीय सरकार के सामर्थ्य को महसूस कर रहा और यह समझ रहा है कि देश किसी अन्य राष्ट्र पर निर्भर नहीं है। उनकी यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच जारी सैन्य गतिरोध के बीच आई है। उन्होंने कहा, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र पहले आता है। कोई भी हित (व्यक्तिगत, राजनीतिक या आर्थिक) राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकता। मौजूदा स्थिति का जिक्र किए बिना उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज हर भारतीय सरकार के सामर्थ्य, दृष्टि और सोच को जान



रहा है। धनखड़ ने कहा कि आज भारत इस मामले में किसी देश पर निर्भर नहीं है और आज देश में जो कुछ हो रहा है, वह हर भारतीय का उत्साह बढ़ा रहा है।

उन्होंने यह टिप्पणी हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा के विमोचन के दौरान की।

पंजाब पहले भी लड़ा है और अब भी आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा: भगवंत मान

पंजाब, 10 मई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों पर कहा कि हम पहले से तैयार थे। पंजाब ने पहले भी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी है और इस बार भी पंजाब ही आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा। फिरोजपुर की घटना में जो लोग घायल हुए हैं (पाकिस्तान ड्रोन हमले में घायल 3 लोगों का परिवार), उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंत्री चीमा वहां गए हैं। मैं कल उन इलाकों का दौरा करूंगा जहां मिसाइलें मिली हैं। मैं लोगों से मिलूंगा। चबराएं नहीं, कुछ भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। वहीं, आज सुबह भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य संघर्ष के बीच पंजाब के पठानकोट तथा



जालंधर जिलों में विस्फोट जैसी आवाजें सुनी गईं और होशियारपुर, अमृतसर और फिरोजपुर जिलों में सायरन बजने लगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हरियाणा के सिरसा में भी कुछ स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आधी रात के बाद विस्फोट जैसी आवाजें सुनीं। अधिकारियों ने बताया कि जालंधर जिले के कंगनीवाल गांव में एक अज्ञात प्रक्षेपास्त्र एक रिहायशी

इलाके में गिरा। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस घटना में एक प्रवासी मजदूर घायल हो गया, जबकि इलाके के कुछ मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि अज्ञात वस्तु के हिस्से इलाके में पड़े हुए हैं। इलाके की एक महिला ने बताया, मैं खिड़की के पास खड़ी थी तभी देर रात करीब डेढ़ बजे कोई चीज पानी की टंकी (घर की) से टकराई, जिससे चार से पांच घरों के शीशे टूट गए। उन्होंने बताया कि एक प्रवासी मजदूर के हाथ में चोट आई है, जिसे अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय निवासी सतिंदर कुमार ने कहा, हमारे घर की पानी की टंकी को नुकसान पहुंचा है, जबकि कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। चारों तरफ धुआं ही धुआं था।

नई दिल्ली, 10 मई। भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम समझौते के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत कड़ी कार्रवाई करना जारी रखेगा। विदेश मंत्री की यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौते पर पहुंचने के बाद आई है, जो दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के लगभग दो दिन बाद हुआ है। शुक्रवार रात को पाकिस्तान द्वारा भारत पर मिसाइलों और तुर्की निर्मित



300-400 ड्रोन से हमला किए जाने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच टकराव और बढ़ गया। दोनों देशों ने शनिवार, 10 मई को शाम 5 बजे से जमीन और हवा में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य अभियान रोकने पर

सहमति जताई है। भारत की ओर से विदेश मंत्री विक्रम मिसरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पाकिस्तान की ओर उसकी सेना के डीजीएमओ ने तनाव कम करने के लिए भारतीय सेना के

डीजीएमओ से संपर्क किया। इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर युद्धविराम के लिए राजी हुआ। दोनों देशों के डीजीएमओ युद्धविराम को लेकर आगे की कार्रवाई के लिए 12 मई को फिर से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान

सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने भारत से संपर्क किया और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सीधे बातचीत की गई। सरकार ने कई दिनों की सैन्य कार्रवाई और दोनों पड़ोसियों के बीच बढ़े तनाव के बाद युद्ध विराम की पुष्टि की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में एक लंबी रात की बातचीत के बाद, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को सामान्य बुद्धि और महान बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

जिला जज और जिलाधिकारी ने लोक अदालत का उद्घाटन किया

राष्ट्रीय लोक अदालत में 66 श्रमवादों का निस्तारण, 99 श्रमिक लाभान्वित
सुलह-समझौते पर सुलाझेंगे लंबित मामले : जिला जज सुरेश गांधी
वाराणसी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वाराणसी के तत्वावधान में शनिवार को युनियन बैंक से संबंधित प्री-लिटिगेशन के मामलों के निस्तारण हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत का उद्घाटन जिला जज जयप्रकाश तिवारी एवं जिलाधिकारी सच्येंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया। राष्ट्रीय



लोक अदालत में कुल 66 श्रमवादों का निस्तारण किया गया, जिसमें 99 श्रमिक लाभान्वित हुए। इस मौके पर जिला जज ने कहा, आपसी सुलह से आती है स्थायी शांति। उन्होंने पक्षकारों से सकारात्मक रूप से मुकदमों का निस्तारण कराने की अपील करते हुए कहा कि सुलह के आधार पर

विवादों का निपटारा सबसे सर्वोत्तम उपाय है। बता दें, अदालत के आयोजन में आने वाले दोनों पक्षों के बैठने, शुद्ध पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था कराई गई। लोक अदालत का मकसद न्यायपालिका के कार्यभार को कम करने तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में वैकल्पिक

विवाद समाधान की दक्षता को उजागर करती है। लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा होता है। यह ऐसा प्लेटफार्म है, जहां समझौते के आधार पर दोनों पक्ष विजयी होते हैं। जिलाधिकारी के आदेश अनुपालन में अपर श्रमायुक्त कार्यालय, वाराणसी क्षेत्र राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप श्रमायुक्त धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों सहित 66 श्रमवादों का निस्तारण किया गया, जिससे कुल 99 श्रमिक धनराशि रुपये 1,67,79,871 से लाभान्वित हुए।

हमारे पूर्वजों ने दो-देश सिद्धांत को खारिज कर दिया था, पाकिस्तान पर बरसे ओवैसी, तुर्की को भी लपेटे में लिया

हैदराबाद, 10 मई। पाकिस्तान के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए वाहवाही बटोर रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पड़ोसी देश को एक और करारा जवाब दिया है। और इस बार इसमें पाकिस्तान के भाई राष्ट्र तुर्की को भी शामिल किया गया है, जो उसे अटूट समर्थन दे रहा है। ओवैसी, जो पहले पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर देखे गए थे, ने अब तुर्की पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि एक तरफ तुर्की अपनी जमीन पर आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है, वहीं



दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन करता है, जिसे आतंकवाद का वैश्विक केंद्र माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें तुर्की को यह समझाना होगा। यह दुनिया का एकमात्र देश है जो अपनी जमीन पर आतंकवादी संगठनों, कुर्द समूहों पर बमबारी करता है। जब

तक उन्होंने इराक के साथ समझौता नहीं किया था, तब तक वे वहां भी आतंकवादी संगठनों पर बमबारी करते थे। और अब वे सीरिया में भी ऐसे शिविरों पर बमबारी कर रहे हैं। इसलिए उनसे पूछा जाना चाहिए कि जब वे विदेशी जमीन पर आतंकवादियों को मार सकते हैं, तो वे भारत से कैसे सवाल कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि हमारी जमीन पर हमले हो रहे हैं, सैनिकों पर, उन्हें लोन मिला है। शासन-प्रशासन तो छोड़िए, उन्हें अर्थव्यवस्था चलाणा भी नहीं आता।



अरुणोदय सर्जिकल एण्ड ट्रामा सेन्टर



जनरल सर्जरी
स्त्री एवं प्रसूति रोग
आर्थोपेडिक (सर्जरी एवं परामर्श)
कीमोथेरेपी सुविधा उपलब्ध
न्यूरो सर्जरी (परामर्श एवं सर्जरी)

वेन्टिलेटर एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध
प्रशिक्षित डाक्टर स्टाफ तथा सभी मानकों पर सरा उतरे वाला जनपद का एक मात्र हास्पिटल
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार की सर्जरी
जनरल मेडिसिन, मधुमेह रोग

गुर्या एवं मूत्र रोग (सर्जरी एवं परामर्श)
गैस्ट्रोइन्टेरोलॉजी (इण्डोस्कोपी एवं कालोनेस्कोपी)
एक्सर्टीडेण्टल एवं ड्रामा इमरजेन्सी सेवा 24 घण्टे उपलब्ध

डा० पुनीत सिंह
M.S.M.C.H.
गुर्या एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ (रुग्ने सर्जन)

डा० रवि प्रकाश सिंह
M.S. (Ortho)
हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ

डा० प्रभात सिंह
M.D. (Medicine)
कंसल्टेंट फिजिशियन

डा० सुमित कुमार सिंह
M.D. (Neuro Psychiatrist)
मासिक रोग विशेषज्ञ

24/7 Emergency Services

बीमा कार्ड धारकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध

आयुष्मान कार्ड द्वारा निःशुल्क इलाज की सुविधाएं

8090966086, 8090015086
कलीचाबाद, जौनपुर



मोहम्मद दानिश

जिला पंचायत सदस्य

वार्ड न० 10

के भावी प्रत्याशी

विकास खण्ड मोंधी शाहगंज जौनपुर



संकट का व्यापार: महंगाई, मुनाफाखोरी और सरकारी चेतावनी



- डॉ सत्यवान सौरभ

किया है। सवाल यह है कि क्या इन घोषणाओं से वास्तव में कोई फर्क पड़ेगा या फिर यह भी अन्य सरकारी वादों की तरह सिर्फ कागजी सख्ती बनकर रह जाएगी।

इतिहास गवाह है कि जब-जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है, तब-तब न केवल सीमावर्ती इलाकों में, बल्कि पूरे देश में खाद्य पदार्थों और ईंधन की किल्लत का माहौल पैदा हुआ है। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। राजनीतिक लाभ के लिए कई बार जमाखोरी और कालाबाजारी को न केवल नजरअंदाज किया जाता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित भी किया जाता है। सरकारें अक्सर महंगाई और किल्लत को 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के नाम पर सही ठहराती रही हैं। यह एक प्रचलित नीति है कि संकट के समय लोगों का ध्यान भटकाने के लिए देशभक्ति की भावना को उभारा जाता है, लेकिन इसका खामियाजा आम नागरिक को भुगतना पड़ता है।

सरकार द्वारा जारी सख्त निदेशों के बावजूद, जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। अमतौर पर, प्रशासनिक अधिकारी इन्हें गंभीरता से नहीं लेते या फिर स्थानीय व्यापारियों और नेताओं के दबाव में आंखें मूंद लेते हैं। यह एक खुला राज है कि कालाबाजारी करने वाले अक्सर राजनीतिक संरक्षण में फलते-फूलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या प्रशासनिक मशीनरी अपने काम में पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करेगी या फिर यह भी केवल फाड़लों में बंद होकर रह जाएगा।

जब जमाखोरी होती है, तो इसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। महंगाई आसमान छूने लगती है, जरूरी वस्तुएं बाजार से गायब हो जाती हैं, और लोगों को मजबूरी में अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकारें राहत पैकेज और सरसे राहत के साथ फीका पड़ जायेंगी। वास्तविक सुधार तभी जरूरतमंदों तक पहुंचना अक्सर एक चुनौती बन जाता है। इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर जागरूकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को इसका सबसे अधिक खामियाजा उठाना पड़ता है।

सरकार ने साफ कर दिया है कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन क्या यह वादा हकीकत में बदल पाएगा? क्या सरकारी तंत्र इस बार वाकई में सख्त रुख अपनाएगा या फिर यह भी अन्य सरकारी निदेशों की तरह समय के साथ फीका पड़ जाएगा? वास्तविक सुधार तभी संभव है जब सरकार अपने सख्त निदेशों को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाए। हर जिले में वस्तुओं की उपलब्धता और वितरण की पारदर्शी जानकारी दी जाए। इससे आम जनता को वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का पता चल सके और अपवाहों का अंत हो।डिजिटल प्लेटफॉर्म और ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग कर स्टॉक और मूल्य में पारदर्शिता लाई जाए। तकनीकी साधनों का उपयोग करके जमाखोरी और कालाबाजारी की निगरानी करना आज के डिजिटल युग में आसान हो सकता है। देशियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ सार्वजनिक रूप से नाम उजागर किया जाए ताकि लोग इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। जनता को इस लड़ाई में भागीदार बनाया जाए ताकि कालाबाजारी करने वालों की पहचान आसानी से हो सके। सामुदायिक सतर्कता समूहों का गठन किया जाए जो नियमित रूप से बाजार की स्थिति पर नजर रखें। संकट के समय गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी के माध्यम से राहत दी जाए। सिर्फ घोषणाओं से समस्याएं खत्म नहीं होतीं, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियान्वयन से ही सुधार संभव है। अगर सरकार वास्तव में कालाबाजारी पर नकेल कसना चाहती है, तो उसे अपनी नीतियों और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करना होगा। वरना, यह सख्ती भी महज एक 'खोखला नारा' बनकर रह जाएगी। जनता को भी सतर्क रहना होगा, ताकि कोई जमाखोर उनका हक न छीन सके।

केवल आदेश और घोषणाओं से समस्याएं समाप्त नहीं होतीं, बल्कि ठोस और ईमानदार क्रियान्वयन से ही सुधार संभव है। सरकार को यह समझना होगा कि महंगाई और कालाबाजारी का मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक चुनौती भी है। जब तक प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और इच्छाशक्ति नहीं होगी, तब तक जमीनी सुधार की उम्मीद बेमानी है। सरकारी नीतियों का केवल कागजी सख्ती तक सीमित रह जाना न केवल जनता के साथ विश्वासघात है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश के मूल सिद्धांतों का भी अपमान है।

इसके अलावा, आम जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों की पहचान में सहयोग करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना समय की मांग है। सिर्फ आलोचना से समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि सामूहिक प्रयास से ही एक स्वस्थ और समतामूलक समाज का निर्माण हो सकता है। वरना यह सख्ती भी महज एक 'खोखला नारा' बनकर रह जाएगी।

कांपा पाक, इंडियन आर्मी ने खिलौनों की तरह तोड़े चीनी हथियार



अनंज कुमार,लखनऊ

कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन की भी पेशानी पर बल ला दिया है। दरअसल, भारतीय सेना पाकिस्तान को बुरी तरह से सबक सिखा रही है तो चीन की चिंता इस बात को लेकर है कि इस युद्ध में चीनी हथियारों की पोल खुलती जा रही है,पाकिस्तान द्वारा दांगी जा रही चीनी मिसाइल और ड्रोन को भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से एक के बाद एक धराशायी करती जा रही है। सेकेंडो चीनी मिसाइलों को इंडियन आर्मी हवा में ही मार गिरा चुकी है। संभवता इसी के चलते पाकिस्तान की बौखलाहट के साथ ड्रैगन यानी चीन की चिंता बढ़ी हुई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान से शांति की अपील करते हुए ज्ञान दिया कि बात अगर बढ़ी तो किसी के हित में नहीं होगा। ऐसा करते हुए उसने पाकिस्तान पोषित आतंकवाद पर चुप्पी साधे रखी। बहरहाल, चीन ने भारत और पाकिस्तान को बातचीत के मेज पर वापस आने की सलाह देते हुए कहा कि वह मध्यस्थता करने का इच्छुक है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रवक्ता ने कहा, हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं कि शांति और स्थिरता के हित में संयम और शांति बरतें और शांतिपूर्वक साधनों से राजनीतिक सुलह के रास्ते पर वापस आएँ। किसी भी ऐसे ऐक्शन से बचें जो तनाव को और ज्यादा बढ़ाएं। यह भारत और पाकिस्तान दोनों के हित में होगा और क्षेत्र तक शांति स्थिरता के लिए आवश्यक है। वैश्विक समुदाय भी इसी की उम्मीद कर रहा है। इसे खत्म कराने के लिए चीन भूमिका निभाने का इच्छुक है।

गौरतलब है कि चीन अपने फायदों के लिए पाकिस्तान को सबसे करीबी दोस्त होने के भ्रमजाल में फंसाए हुए है। चीन ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। भारत के रुख और सैन्य ताकत को देखते हुए चीन को अब अपने प्रॉजेक्ट्स पर भी असर होने का अदेशा होने लगा है। आतंकवाद को लेकर हमेशा चीन का बचाव करता रहा ड्रैगन अब उसकी ऑफेंसिव देख झाड़ूा रोकने की इच्छा जाहिर कर रहा है।

उधर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत में हमले की नाकाम कोशिशें की हैं तो दूसरी जवाबी कार्रवाई में उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत ने पाकिस्तान के चार एयरबेस को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है।



-अशोक भाटिया

ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 मई की आधी रात के बाद भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई बहादुर कार्रवाई के नतीजे अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। इसकी कार्रवाई की प्रकृति सीमित, संयमित लेकिन प्रभावी है। यह जलन और जलन पिछले 36 घंटों से पाकिस्तान की कार्रवाइयों में परिलक्षित होती है। इन सभी हमलों को ड्रोन और हल्की मिसाइलों द्वारा सफलतापूर्वक रद्द कर दिया गया था। वहाँ हैं। इसके लिए सरकार और सशस्त्र बलों को बधाई। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू-कश्मीर सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। ड्रोन हमले सीमावर्ती राज्यों जम्मू, पंजाब और राजस्थान में किए गए। रात के अंधेरे में हवा में इन ड्रोनो को नष्ट करने में, सशस्त्र बलों और विशेष रूप से वायु सेना ने हथियारों का प्रदर्शन किया।

इसके अलावा, सिर पर ड्रोन का घर, हवाई हमलों की चेतावनी देने वाली भोंग, रोशनी सभी जगह थी। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, हमारे सशस्त्र बलों और सरकार ने भी धुंध के अंधेरे के माहौल में सीमावर्ती शहरों में प्राकृतिक भय से पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से, हमारे सशस्त्र बलों और सरकार ने प्राकृतिक भय से पीड़ित लोगों को आश्वस्त भी किया है। यह दृढ़ संकल्प और धैर्य दिखाता है। भले ही हमारे कई इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनल धैर्य का प्रयोग करें, लेकिन देश भर में ध्वनि प्रदूषण और अज्ञानता प्रदूषण बहुत कम होने की संभावना है। यह कार्रवाई जितनी हमारे सशस्त्र बलों की तत्परता और सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, उतनी ही यह ऐसी गतिविधियों की रिपोर्टिंग में हमारे खुलेपन और अपर्याप्तता को भी उजागर करती है, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक समाचार चैनलों के। हमारे पास प्रचार के लिए आवश्यक सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की कमी कभी नहीं थी, और दर्शकों को जो जानकारी दी जा रही है, उसे देखते हुए, यह तय करना मुश्किल है कि उनकी कल्पना की प्रशंसा करें या उनकी मानसिक और नैतिक गिरावट पर शोक मनाएं।

रात के अंधेरे में, भारतीय वायु सेना और सेना ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों, हवेली और उनके नेताओं के मुख्यालयों का दौरा किया। उन्होंने इस तथ्य पर विशेष ध्यान दिया कि सटीक हमलों या सटीक हमलों के रूप में सैन्य प्रतिष्ठानों और नागरिक बस्तियों को कोई नुकसान नहीं होगा।

भारत के लिए, मुद्दा वहीं समाप्त हो गया, क्योंकि पहलगाम हमला पाकिस्तानी की आक्रामकता थी और ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब था। हम मानते हैं। फिर भी पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन हमले करने की गलती की और अब यह वास्तव में उनके लिए महंगा है। क्योंकि भारत ने सफलतापूर्वक उनके हथियारों को दोहराया; लेकिन दूसरी ओर, भारतीय ड्रोन और हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान के पास समान कुशल रक्षा प्रणाली नहीं है। यानी भारत जब भी संभव हो हमलों और हमलों को रोक सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे बहुत

आगे निकल गया, उनमें से कुछ ने 'भारतीय नौसेना द्वारा कराची के विनाश' पर रिपोर्टिंग की। कुछ लोगों का दृढ़ विश्वास था कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर तुर्की भाग गए थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रतिस्थापित किए गए सज्जन का नाम भी सामने आया था। कुछ का मानना ​​है कि 'भारतीय सैनिकों ने एलओसी पार कर एक के बाद एक पाकिस्तानी शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।' उन्होंने कहा, 'कोई चिल्ला रहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया है। व्यक्ति को शायद अपनी आवाज को लाइन में लाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी और सियालकोट भारत के हाथों में गिर गए। सेना, वायु सेना और नौसेना ने पाकिस्तान को नष्ट कर दिया। उनमें से एक चिल्लाया, बलूच विद्रोही बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर भाग गए। अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग समय पर शूट किए गए दृश्यों को पाकिस्तान में एकत्र किया गया और दिखाया गया। रात में मीडिया में शोर चल रहा था, 8 मई की आधी रात, फिर 9 मई को पूरा दिन। बुखार इस हद तक बढ़ गया कि रक्षा मंत्रालय को आखिरकार नोटिस जारी करना पड़ा। रजिम्पेडारी से रिपोर्ट करें। किसी भी परिस्थिति में सशस्त्र बलों की कार्य योजनाओं या आंदोलनों को इस तरह से नहीं दिखाया जाना चाहिए जो दुश्मन को दिखाई दे। सरकार को अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपील करनी होगी कि वह याद करे कि कारगिल युद्ध और मुंबई आतंकी हमले के दौरान ऐसी भावना का पालन नहीं किया गया था।

आपातकाल की स्थिति में भी सरकार को इस गैरजिम्मेदारी पर

युद्ध से युद्धविराम तक: भारत-पाक रिश्तों की बदलती तस्वीर



- प्रियंका सौरभ

भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच की सीमाएं न केवल भौगोलिक हैं, बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन भी हैं, जो 1947 में विभाजन के समय से आज तक खिंची हुई हैं। इस तनाव का सबसे बड़ा कारण जम्मू-कश्मीर का मुद्दा

रहा है, जो आज भी विवाद का मुख्य बिंदु है।

1947-48: पहला युद्ध

और पहला युद्धविराम

भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947-48 में हुआ, जिसे कश्मीर युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान समर्थित कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला किया। भारतीय सेना ने महाराजा हरि सिंह की सहायता के लिए कश्मीर में प्रवेश किया, जिसके बाद संघर्ष बढ़ता गया। इस युद्ध का अंत 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद हुआ, जिसने युद्धविराम की घोषणा की और दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा (LoC) स्थापित की। यह युद्धविराम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 47 के तहत हुआ था, जिसमें कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई थी, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया।

1965 का युद्ध और ताशकंद समझौता

1965 में, कश्मीर मुद्दे पर फिर से संघर्ष भड़क उठा। इस बार पाकिस्तान ने 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' शुरू किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में घुसपैठ की। भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया और युद्ध पंजाब, राजस्थान और कश्मीर में फैल गया। इस युद्ध का अंत 23 सितंबर 1965 को हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ के मध्यस्थता के बाद ताशकंद समझौता हुआ। इस समझौते पर 10 जनवरी 1966 को भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए।

1971 का युद्ध और शिमला समझौता

1971 का युद्ध मुख्य रूप से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हुआ था। पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच तनाव बढ़ता

गया और पूर्वी पाकिस्तान (आज का बांग्लादेश) में स्वतंत्रता की मांग ने युद्ध का रूप ले लिया। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को निर्णायक हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ, जिसमें दोनों देशों ने सभी विवाद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का वादा किया और नियंत्रण रेखा (छद्मउ) की स्थापना की गई।

1999 का कारगिल युद्ध

कारगिल युद्ध 1999 में हुआ, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने कारगिल-ड्रास सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। इस संघर्ष में दोनों देशों के बीच भीषण लड़ाई हुई और कई सैनिकों ने अपने प्राणों का आहुति दी। यह युद्धविराम 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, जब भारत ने अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया।

में, सरकार को सहकारी नागरिकों और जिम्मेदार मीडिया के समर्थन की आवश्यकता है। प्रिंट मीडिया ने उस जागरूकता को ज़्यादातर दिखाया है, लेकिन जिम्मेदारी और चेतना शब्द उनके शब्दकोश से गायब हो गए हैं। उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उस तरह की तात्कालिकता नहीं दिखाई है।

कहा जाता है कि युद्ध में पहली दुर्घटना सच्ची जानकारी होती है। यह दुनिया भर के सभी युद्धों के इतिहास में कमोबेश देखी जाती है। सच्ची जानकारी प्राप्त करना मुश्किल है, झूठी सूचनाओं की बाढ़ आदि। या द्वितीय विश्व युद्ध में नाजियों और सहयोगियों द्वारा व्यापक प्रचार; इसमें दिखाया गया है कि कैसे सूचना को युद्ध में हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

समकालीन युद्धों में यह और भी अधिक स्पष्ट है, क्योंकि ये युद्ध न केवल युद्ध के मैदान पर खेले जाते हैं, बल्कि जनमत के युद्ध के मैदान पर भी खेले जाते हैं। सभी स्तरों पर, युद्ध की पृष्ठभूमि, युद्ध का समर्थन और युद्ध के बाद स्थापित होने वाली कथा, शासकों को जनमत पर भरोसा करना पड़ता है, जैसे युद्ध की कहानियों के साथ-साथ युद्ध के सही तथ्यों को भी बताया जाना चाहिए। मीडिया और भार से भरे आज के समय में, कार्य चुनौतीपूर्ण है। 1960 के दशक में, संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल वियतनाम के युद्ध के मैदान पर, बल्कि अमेरिकी मीडिया ने उत्पादित सूचना और कथा पर युद्ध में भी हार गया, इससे सीखते हुए, 1990 के दशक के पहले खाड़ी युद्ध में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल समाचार मीडिया भागीदारी का एक समूह बनाया। एम्बेडेड पत्रकारिता, या रआश्रित पत्रकारिता, युद्ध पत्रकारिता का एक नया रूप था।

सूचना का खराब उपयोग युद्ध या किसी भी सशस्त्र संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ताजा भारत-पाकिस्तान संघर्ष में भी यह साफ है कि सूचना युद्ध लड़ना कितना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है।

पाकिस्तान की दुनिया कभी भी एक विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में नहीं जानती थी। पहलगाम पर आतंकवादी हमले के बाद भारत की बहुत ही सटीक, संयमित और मर्मज्ञ कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान का झूठ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। भारत की कार्रवाई की सफलता, भारतीय सेना द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबूतों के साथ दी गई स्पष्ट, सटीक जानकारी, वास्तविक युद्धक्षेत्र हमले में खुद को कायम नहीं रख पाई। यह बात साफ होते ही पाकिस्तान ने सूचना के रणक्षेत्र में भारत पर हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया और खासकर सोशल मीडिया ने गलत जानकारी फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने वीडियो और तस्वीरों का उपयोग करके पोस्ट बनाए, जिनका नवीनतम संघर्षों से कोई लेना-देना नहीं था, उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रसारित किया गया और मंत्रियों और अधिकारियों को उनका उपकाय करने, उन सभी का मुकबला करने, अपने झूठ और इस तरह के पोस्ट दिखाने के लिए कहकर उन पर कुछ वैधता की मुहर लगाने की कोशिश की। भारत को अपने उपयोगकर्ताओं का भारतीय डिजिटल स्पेस से हटाने के लिए एक और नया अभियान शुरू करना पड़ा। और ऐसा नहीं है कि वह तब तक जारी रहेगा जब तक 'ऑपरेशन सिंदूर' जारी रहेगा और शायद उसके बाद भी।

-अशोक भाटिया

होने देते।

2025: नवीनतम युद्धविराम और वर्तमान स्थिति

10 मई 2025 को, भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्ण और तत्काल युद्धविराम पर सहमति व्यक्त की, जो हाल के वर्षों में सबसे गंभीर संघर्ष के बाद हुआ। यह संघर्ष 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के बाद शुरू हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई, जिसमें मिसाइल और ड्रोन हमले शामिल थे।

संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद, दोनों देशों ने युद्धविराम पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा करते हुए दोनों देशों की सरहना की। हालांकि, इस युद्धविराम के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे कि सिंधु जल संधि का निलंबन और सीमा पर तनाव।

सेना के साथ खड़ा भारत, सत्ता के लिए लड़ता पाकिस्तान



-संजय सक्सेना

हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में जिस तरह से सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर तलवारें खिंचीं नजर आती थीं,उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से दोनों धड़ों में एकजुटता देखने को मिल रही है,उससे देश की आम जनता काफी खुश है,वहीं पाकिस्तान में इसके उलट नजारा नजर आ रहा है। पड़ोसी मुल्क में विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसने और उन्हें नाकाबिल नेता साबित करने में लगा है। मोदी और शरीफ की तुलना शेर और सियार के रूप में की जा रही है।

बहरहाल,भारत के लिये यह सुखद है कि आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार के हर कदम पर विपक्ष बिना किसी शर्त के पूरी मजबूती से खड़ा है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके जताब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक अद्भुत परिवर्तन देखा गया है। विपक्षी दलों ने इस बार न केवल सरकार का समर्थन

किया बल्कि सेना के साहस और कार्रवाई की खुलकर सराहना की। इससे पहले उरी और पुलवामा हमलों के बाद जिस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, और बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी खांचे में रखकर सियासी नुकसान पहुंचाया था, उस पृष्ठभूमि में यह बदलाव बेहद अहम है। यह न केवल राजनीति की परिपक्वता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भारत अब एक स्वर में बोल रहा है। गौरतलब हो, 22 अप्रैल के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले ने न केवल आम जनता की भावनाओं को आहत किया, बल्कि विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती खड़ी कर दी थी कि वे इस मुद्दे को किस रूप में लें। कांग्रेस और अन्य प्रमुख दलों ने बिना देर किए केंद्र सरकार को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की। इससे भी बड़ा बात यह थी कि उन्होंने सुरक्षा और खुफिया तंत्र की संभावित चूक का मुद्दा उठाने के बावजूद, इसे राजनीति का विषय नहीं बनने दिया। यह देश की एकता और संप्रभुता की रक्षा के लिए विपक्ष का एक परिपक्व और जिम्मेदार रवैया था।

भारतीय सेना ने इस हमले के जवाब में पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सटीक और प्रभावशाली कार्रवाई की। सेना की इस जवाबी कार्रवाई को विपक्ष की ओर से न केवल समर्थन मिला बल्कि सराहना

भी हुई। कोई सवाल नहीं, कोई प्रमाण की मांग नहीं, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं बस एक सुर में सरकार और सेना के साथ खड़े रहने की भावना। ह्दभारत माता की जयह्व और ह्रजय हिंदह्व के नारों के साथ विपक्षी नेता भारतीय सेना के साथ नजर आए। यह एक ऐसी तस्वीर थी जो 2016 के उरी हमले या 2019 के पुलवामा हमले के बाद नजर नहीं आई थी।

उरी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने उस पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्र विरोधी के तौर पर पेश करके राजनीतिक लाभ उठाया था। ठीक ऐसा ही पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान हुआ था। कांग्रेस ने तद्विजय सिंह ने सबूत मांगे थे, जिसके चलते पार्टी को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी ने भी सेना के शौर्य पर विश्वास जताने के साथ-साथ पीपुस मोदी पर जवानों के बलिदान की राजनीति करने का आरोप लगाया था। इन बयानों से कांग्रेस को चुनौती मैदान में भारी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन इस बार कहानी बदली हुई है।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को रोक दिया, पार्टी की सर्वोच्च नीति-निर्धारण संस्था कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक बुलाई गई और राहुल गांधी ने स्वयं सेना को समर्थन देने का ऐलान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा के सुझाव पर कांग्रेस ने अपनी प्स्थिधान बचाओरैली स्थिति कर

दी, ताकि सेना के प्रति एकजुटता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश स्पष्ट रूप से जाए। यहां तक कि कर्नाटक कांग्रेस ने भी अपनी उस सोशल मीडिया पोस्ट को हटा दिया, जिसमें शांति को सबसे बड़ा हथियार बताया गया था जो शायद मौजूदा माहौल में सेना के ऑपरेशन के संदर्भ में जलत संदेश दे सकती थी।

कांग्रेस के इस नए रुख के साथ ही अन्य विपक्षी दल भी उसी दिशा में नजर आए। वसुंधरी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से बात करके अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने की घोषणा की। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे ए के अंटील, जो अक्सर मोदी सरकार के आलोचक रहे हैं, उन्होंने भी ऑपरेशन सिंदूर को ह्वाएक मजबूत शुरूआतह्व बताया और सेना की निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जो पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी के शब्दों की आलोचना कर चुके थे, उन्होंने भी इस बार सेना के साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि पूरा देश एकजुट है।हाष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की खुलकर सराहना की और जवानों की सलाम किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो अक्सर मोदी सरकार के आलोचक रहते हैं, उन्होंने भी इस बार सरकार के सुर में सुर मिलाया और पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई की प्रशंसा की।

यहां तक कि वामपंथी दलों ने, जो आमतौर पर सैन्य कार्रवाई पर संयम बरतने की बात करते हैं, उन्होंने भी पहलगाम हमले के बाद सरकार और सेना के साथ खड़े होने की बात कही। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) ने भी माना कि इस बार भारत के पास जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

यह पूरा घटनाक्रम भारतीय राजनीति के लिए एक नई दिशा का संकेत है। यह दशर्ता है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर अब राजनीतिक दल न केवल एकजुट हैं, बल्कि अपने पुराने सियासी रवैये की भी समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का यह नया रुख जहां उसे राष्ट्रवादी विमर्श में खुद को फिट करने में मदद करेगा, वहीं अन्य विपक्षी दलों के लिए भी यह संदेश है कि जनता अब केवल आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि एकजुटता और जिम्मेदारी की राजनीति देखना चाहती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी नीति न तो नरम है, न ही विभाजित। यह केवल केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम नहीं, बल्कि विपक्ष की परिपक्व भागीदारी का भी प्रतिबिंब है। अगर इस रुख को बंधिय में भी कायम रखा गया, तो यह न केवल देश की आंतरिक राजनीति को परिपक्व बनाएगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत की छवि को और सुदृढ़ करेगा।

बात पाकिस्तान की कि जाये तो वहां सेना,सरकार और विपक्ष के

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन ने की मनपा की अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी के साथ बैठक मुंबई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंदभाई परमार के नेतृत्व में मुंबई महानगरपालिका की अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। मनपा की इस संयुक्त बैठक में सभी यूनियनों ने मुंबई महानगरपालिका के सफाई कर्मचारियों का मुद्दा उठाया। बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन (60) के मुंबई सचिव जीतूभाई रोड की ओर से मुंबई महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान सफाई कर्मचारियों के मुद्दे के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया कि 12.8.1975 को महाराष्ट्र सरकार की ओर से लाड पागे समिति की स्थापना की गई। जबकि मनपा में 2005 में उसके नियम को अमल में लाया गया गया। यूनियन ने मांग की है कि समिति की सिफारिशों को सभी वार्डों और सभी विभागों में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 1995 के आदेशानुसार सभी विभागों में ठेका प्रथा बंद की जाए तथा सभी विभागों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। (ठेका पद्धति भगाओ, वारिस हक्क नौकरी को भगाओ) तथा लाड पागे समिति की सिफारिसों में मल निकासी, मुख्य मल निसारण, गटर, मेंसुर, खाता, माली जैसे सभी कर्मचारियों व कामगारों को लाड पागे समिति का लाभ मिलना चाहिए। सुबह ११ बजे से १ बजे तक चली इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश टोकेकर, राष्ट्रीय सचिव एस. लीना डिसूजा, मुंबई अध्यक्ष एड. रवि गवली, मुंबई उपाध्यक्ष नवीनचंद्र मकवाना, श्रीमती मनोभा ताई खाखडिया, सचिव जीतूभाई रोड, विलास दिवेकर, मारुति कांबले, गायकवाड़, तथा अन्य सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं अधिकारियों में मुंबई महानगर पालिका की अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी (शहर), डीएमसी (घन कचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर, मुख्य कामगार अधिकारी सुनील जागली मुख्य अभियंता प्रशांत पवार , सामान्य प्रशासन के किशोर गांधी मुख्य पर्यवेक्षक प्रवीण सांगली संयुक्त मुख्य पर्यवेक्षक सुराडकर के साथ-साथ मनपा के सभी विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अंत में गोविंदभाई परमार के द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता हेतु संगीतमय सुंदर काण्ड पाठ संपन्न



मुंबई (उत्तरशक्ति)। घाटकोपर वेस्ट के अमृतनगर स्थित संकट मोचन हनुमान मंदीर पर जनसेवा वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में शनिवार को संगीतमय सुंदर काण्ड पाठ का आयोजन किया गया। गौरतलब है यह सुंदर काण्ड पाठ यशस्वी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद हमारी भारतीय सेना आगे भी यशस्वी हो। ढ0' भारत का हिस्सा बने।और भारत के सैनिकों को ताकत मिले इसी मनोकामना के साथ संगीतमय सुंदर काण्ड पाठ. हनुमान चालीसा और भजन का सुंदर आयोजन हमारी भारतीय सेना तथा समस्त जनमानस के कल्याण हेतु किया गया जिसमे भजन गायक विमलेश मिश्र,पप्पु त्रिवेदी की टीम ने बहुत ही मार्मिक भजन से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया. इस अवसर पर श्री रामलीला उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल, दीनानाथ सिंह,ट्रस्ट अध्यक्ष अरविंद शुक्ल, दिनेश सिंह, राजन सिंह, राजेश सिंह, चंदमणि सिंह, राकेश दुबे, प्रेम तिवारी,मंदीर पुजारी संतोष सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।

खिचड़ी घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल, उद्धव ठाकरे के करीबी का भी नाम



मुंबई। कोविड महामारी के दौरान इटउ की खिचड़ी वितरण योजना में 14.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी मामले में शुक्रवार को 8 आरोपियों के खिलाफ किला कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और सरकारी रेकॉर्ड में फजीवाड़े के गंभीर आरोप लगे थे, जिनकी विस्तृत जांच के बाद एडह ने यह चार्जशीट दायर की है। शिकायत कल्याण में रहने वाले गोपाल पांडुरंग लवाने (36) ने दर्ज कराई थी, जो श्री वैष्णवी किचन और सहाद्री रिफ्रेशमेंट के साझेदार हैं।

शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2020 से जुलाई 2020 के बीच कोविड संकट के दौरान आरोपियों ने 100-200 ग्राम वजन के पैकेटों की आपूर्ति की और इटउ से 300 ग्राम प्रति पैकेट के हिसाब से भुगतान वसूला। इसमें 6.27 करोड़ रुपये का घपला किया।

आठ आरोपियों सुनील कदम उर्फ बाला कदम, राजीव सालुंखे, सुजीत पाटकर, संजय चंद्रकांत माशेलकर, प्रांजल माशेलकर, प्रीतम माशेलकर, सूरज चव्हाण और अमोल गजानन कीर्तिकर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आरोपियों ने जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे, इसलिए मामले में आईपीसी की धारा 465, 468, 471 (जालसाजी और दस्तावेजों में फर्जीबाड़ी) भी जोड़ दी गई है।

उत्तरशक्ति

* संपादक: ओमप्रकाश प्रजापति
* उप संपादक: प्रेम चंद मिश्रा
*प्रबंध संपादक: डा. शेषधर बिन्द
उपरोक्त सभी पद अवैतनिक है।
पत्राचार कार्यालय :
उत्तरशक्ति (हिंदी दैनिक)
मुंबई-पूणे मोटर मालक श्रमजीवन प्रिमायसेस को.सो., बी-5, ए-337 ट्रक टर्मिनल डब्लू.टी.टी. रोड, आर.टी.ओ. जबल, ऑटफ हिल वडाला, मुंबई-37
मो.- 9554493941
email ID- uttarshaktinews@gmail.com

प्रजापति 93245 26742
फॅब्रीकेशन अॅण्ड गिल ववर्स 98200 55193
93227 55403

PRAJAPATI
FABRICATION & GRILL WORKS

MANUFACTURERS OF
COMPOUND GATES, MS GRILLS, WATER TANKS,
ROLL SHUTTER, COLLAPSIBLE DOOR &
ALLUMINIUM SLIDING WINDOW

SHOP NO. 101, SAVERA CHS., LAST BUS STOP, VEERA DESAI ROAD,
ANDHERI (W), MUMBAI-400053. GST No. : 27ANKPP6297R12P

भिवंडी में युद्ध जैसे आपात स्थित से निपटने के लिये किया गया मॉकड्रिल अभ्यास

आचार्य सूरजपाल यादव भिवंडी (उत्तरशक्ति)। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किये गए हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर झोन हमले शुरू कर दिये। भारतीय सैनिकों ने इसका मुहताज जवाब दिया जिससे युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। आम लोगों को इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारियों की जांच करने के लिए केंद्रीय गृह विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑपरेशन अभ्यास नामक एक

सेना की कामयाबी व आतंकवाद के खत्म के लिए हिंदू जनजागृति संस्था के महिला प्रखंड ने किया पूजन हवन



पालघर(उत्तरशक्ति)। भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य संघर्ष के बीच बोईसर के हनुमानजी मंदिर में आतंकवाद के खत्मे,सशस्त्र बलों के कामयाबी और देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना एवं हवन किया गया हैं। हिन्दू जनजागृति संस्था की राष्ट्रीय संगठन मंत्री तुलसी छीपा ने बताया कि आतंकवाद के खत्मे के लिए मंदिर में हवन, आरती और प्रार्थना कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा, शक्ति और

महाराष्ट्र सरकार ने मछुआरों को समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को पालघर तट पर काम करने वाले मछुआरों को सुरक्षा निर्देश जारी किए और उनसे भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहने को कहा। यहां एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि तटीय निगरानी बढ़ाने के संबंध में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि मछुआरों की अधिकतर नौकाएं ट्रांसपोंडर से



सुसज्जित हों ताकि उनके स्थानों पर नजर रखी जा सके। सरकारी अधिकारी ने बताया कि प्राधिकारियों ने पालघर तट के पास दो स्थानों की पहचान की है - जो मुंबई के उत्तर में स्थित है और जहां मछुआरे नियमित रूप से एकत्र होते



। युद्ध जैसी स्थिति के दौरान नागरिकों को अधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि वे बिना घबराये या अराजकता फैलाये एक ही स्थान पर रहें। इसके बाद आपातकालीन स्थिति में नागरिकों

या घायलों की मदद कैसे की जाए इस पर प्रदर्शन किए गए। इस स्थान पर नागरिकों को हवाई हमलों और बम हमलों की सूचना दी गई। ऐसी स्थिति में सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर

पहुंचने के निर्देश दिए गए तथा बिना भागे या शोर मचाए नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने संबंधित क्षेत्र में सर्वे अभियान चलाने तथा घायल व फंसे हुए नागरिकों को तुरंत बचाने तथा उन्हें

प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने आदि के बारे में प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। यह मॉक ड्रिल जिलाधीश तथा नागरिक सुरक्षा बल नियंत्रक अशोक शिंगारे, अपर जिलाधीश हरिशंकर पाटिल, निवासी उप जिलाधीश डॉ. संदीप माने तथा प्रांतीय दंडाधिकारी अमित सानप के मार्गदर्शन में तहसीलदार अजय घोलवे की पहल पर आयोजित की गई। भिवंडी प्रांतीय मजिस्ट्रेट अमित सानप ने कहा कि

प्रशासनिक व्यवस्था युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और यह मॉक ड्रिल यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत की गई थी कि नागरिकों को बिना घबराए ऐसी स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। नागरिकों में आपातकालीन परिस्थितियों में पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता और आत्मविश्वास को बढ़ाया। इस अवसर पर नागरी संरक्षण दल के उपनियंत्रक के.आर. कुरकुटे, विभागीय क्षेत्र रक्षक दहानू नरेश महस्के, विभागीय क्षेत्र रक्षक पालघर वाडा निलेश वझे, तारापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक अशोक वनसेडे, नागरी संरक्षण दल कार्यालय के कर्मचारी अनिकेत धोड़ी, अनंत पिरकर व स्वनिपल विदे के अलावा बड़ी संख्या नागरी संरक्षण दल के स्वयंसेवक, होमगार्ड, रत्न सागर कॉम्प्लेक्स हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

तारापुर -बोईसर में आयोजित ब्लैकआउट मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक सम्पन्न



और खिड़कियों पर खाकी कागज चिपकाकर शांतिपूर्वक घर के अंदर रहे। करीब दस मिनट के बाद एक समान सायरन ध्वनि द्वारा हवाई हमला समाप्त होने का संकेत मिला, जिसे हरा सिग्नल कहा जाता है। इसके बाद नागरी संरक्षण दल के

उपनियंत्रक के.आर. कुरकुटे ने नागरिकों को प्राथमिक उपचार, आग से बचाव के उपाय तथा ब्लैकआउट से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी। यह आयोजन जिला प्रशासन और नागरी संरक्षण दल के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ। इस ड्रिल ने

ऑपरेशन सिंदूर में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए आगे आया लोढ़ा फाउंडेशन

मुंबई (उत्तरशक्ति)। हमारे वीर सशस्त्र बल 140 करोड़ भारतीयों की आजादी और गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, जिनका देश हमेशा ऋणी रहेगा। उनकी वीरता और बलिदान को सम्मानपूर्वक नमन करते हुए, लोढ़ा फाउंडेशन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए हमारे सैनिकों के परिवारों को निम्नलिखित प्रकार से समर्थन देगा।

- लोढ़ा फाउंडेशन शहीदों के बच्चों की कॉलेज स्नातक तक की शिक्षा का सम्पूर्ण खर्च वहन करेगा। इसमें फीस, किताबें और होस्टल की सुविधाएं शामिल होंगी। इसके अलावा, लोढ़ा जीवन्यस प्रोग्राम के तहत इन्हें उन्नत शिक्षा और मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी।
- शहीदों की पत्नी/पति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किलिंग और उद्यमिता (एंटरप्रेन्योरशिप) का समर्थन दिया जाएगा। यदि वे इच्छुक हों, तो लोढ़ा ग्रुप और लोढ़ा फाउंडेशन में उन्हें रोजगार के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- शहीदों के माता-पिता के लिए अगले 20 वर्षों के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही, देश के वीर सैनिकों और नागरिकों के परिवारों की सहायता के लिए, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने प्राण गँवाए या स्थायी रूप से अपंग हुए, लोढ़ा फाउंडेशन



ने ऑपरेशन सिंदूर / पैट्रियट्स फंड की स्थापना की है इस फंड में प्राप्त सभी दान राशि का उपयोग इन परिवारों के कल्याण हेतु किया

जाएगा। लोढ़ा फाउंडेशन सरकार और सशस्त्र बलों के साथ हरसंभव सहयोग देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है।

मुंबई मेट्रो-3 का देवेंद्र फडणवीस करेंगे उद्घाटन
मुंबई। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) को मेट्रो-3 कॉरिडोर के दूसरे पर मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) का सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है। शनिवार से दूसरे फेज के तहत तैयार बीकेसी से आचार्य अत्रे चौक तक का मेट्रो मार्ग आम यात्रियों के लिए खुल सकता है। यात्रियों के लिए मेट्रो के द्वार खोलने से पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तैयार मेट्रो मार्ग का जायजा लेंगे। मेट्रो के इस फेज के खुल जाने से यात्री आरे से आचार्य अत्रे चौक तक अंडरग्राउंड मेट्रो से सफर कर पाएंगे। इस फेज के खुल जाने यात्री मेट्रो-3 कॉरिडोर के और 6 स्टेशन से सफर कर पाएंगे। कोलाबा से आरे के बीच 35 किमी के मार्ग पर अंडरग्राउंड मेट्रो का निर्माण किया गया है। अक्टूबर 2024 में आरे से बीकेसी के बीच 12.69 किमी के रूट पर मेट्रो सेवा का शुरूआत की गई थी। अब मेट्रो का और 9.77 किमी मार्ग यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए तैयार हो गया है। शनिवार को मेट्रो सेवा वली तक शुरू करने के साथ ही एमएमआरसीएल जुलाई तक पूरे रूट पर सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है।

THE DOCTORS COACHING
Your Gateway to Success in NEET & Foundation Exams!
Powered by- Modern Kids Education Pvt.Ltd. (Since 1999)

NEET (UG) & FOUNDATION
Physics Chemistry Biology

9th, 10th, 11th & 12th
Smart Classes Fully Air-Conditioned Classes

The Doctors Coaching Your Gateway to success in
NEET a foundation exams!
ADMISSION OPEN NOW!

www.thedoctorcoaching.com | edu@thedoctorcoaching.com
+91- 7080403322, +91- 8400043322
Near LHPS, Friends Colony, Sector- 7, Vikas Nagar, Lucknow- 226022

